ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगी डायग्नोस्टिक सुविधाएं

- एमआरआई और एक्स-रे उपकरण लाने की तैयारी
- एआई आधारित उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 02 जुलाई. प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिये नया कदम उठाया है. इसके तहत प्रदेश चिकित्सा तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक अहम समझौता हुआ है. इसके तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित उपकरण सौंपे जाएंगे.

बता दें इस पहल के तहत मध्य प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें और 308 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरण मिलने जा रहे हैं. इनके आने से राज्य में बीमारियों की शुरुआती जांच और सटीक इलाज की क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही इस नई व्यवस्था से प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर अंचलों में रहने वाले नागरिकों को ये सुविधाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेंगी.

इनका कहना है

पीएम केयर्स के माध्यम से उपलब्ध होने वाले आधुनिक डायग्नोस्टिक से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

राजेन्द्र शुक्ल,
उप मुख्यमंत्री, मप्र

पोर्टेबल एक्स-रे से घर के पास जांच

308 एआई-इनेबल्ड हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों की मदद से स्वास्थ्य कर्मी दूरदराज के गांवों में जाकर भी मौके पर ही डिजिटल एक्स-रे कर सकेंगे। एआई तकनीक की वजह से बीमारियों की पहचान तुरंत और सटीकता से हो सकेगी।

कैंसर और गंभीर रोगों की पहचान

11 नई मैमोग्राफी मशीनों की तैनाती से प्रदेश में महिलाओं में स्तन कैंसर की शुरुआती जांच को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 13 नई एमआरआई मशीनों से न्यूरो, रीढ़ की हड्डी और अन्य जटिल शारीरिक समस्याओं की जांच सरकारी स्तर पर रियायती या नि:शुल्क दरों पर हो सकेगी।

एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा इलाज

आरोग्य सेतु 2.0 और आयुष्मान ऐप जैसी डिजिटल प्रणालियों के जरिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और 'आभा' खातों के जरिए मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। इससे मरीजों को हर बार पुरानी पर्चियां और भारी-भरकम फाइलें लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जैसी प्रणालियों से अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज और क्लेम की प्रक्रिया बेहद तेज और पारदर्शी हो सकेगी.

संघ की अहम बैठक 10 से, छाएगा चंदा चोरी का मुद्दा

- भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, शताब्दी समारोह की समीक्षा सहित कार्य विस्तार पर चर्चा होगी

मिलिंद मुजुमदार

इंदौर, 2 जुलाई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक इस बार 10, 11 और 12 जुलाई को कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने जा रही है. सामान्यत: यह बैठक संघ के नियमित संगठनात्मक कार्यक्रमों का हिस्सा होती है, लेकिन इस बार इसकी अहमियत कई कारणों से अधिक बढ़ गई है.

संघ अपने शताब्दी वर्ष (2025-26) के मध्य चरण में है, देश के अनेक राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, भाजपा का संगठनात्मक पुनर्गठन जारी है और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हालिया विवादों ने भी नई परिस्थितियां पैदा कर दी हैं. ऐसे समय में बेलगावी की बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक भी मानी जा रही है. इस बैठक में संघ के सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक भाग लेंगे. इनके साथ संघ प्रेरित 32 विभिन्न संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी उपस्थित रहेंगे. संघ की कार्यप्रणाली में प्रांत प्रचारकों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वे शाखा विस्तार, कार्यकर्ता निर्माण और संगठन के दीर्घकालिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं. बैठक में संघ शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अब तक आयोजित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाएगा. विजयादशमी 20 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शताब्दी वर्ष के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से विचार होगा.

सबकी रहेंगी निगाहें

राजनीतिक दृष्टि से भी बेलगावी की बैठक पर सबकी निगाहें रहेंगी. यद्यपि संघ और भाजपा अपनी-अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना रखते हैं, फिर भी दोनों के बीच संगठनात्मक समन्वय लंबे समय से स्थापित परंपरा का हिस्सा रहा है. भाजपा इस समय कई राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया में है. जानकारी के अनुसार पार्टी ने संघ से कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की मांग की है, जिन्हें विभिन्न राज्यों में प्रांतीय संगठन महामंत्री जैसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. वर्तमान में देश के पांच राज्यों में प्रांतीय संगठन महामंत्री का पद रिक्त बताया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बेलगावी बैठक के बाद इन पदों पर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होता है. यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों और भाजपा की चुनावी तैयारियों पर भी दिखाई दे सकता है.

चंदा चोरी कांड और भाजपा पर भी चर्चा होगी

इस बार बैठक का सबसे चर्चित पहलू संघ के अनुषांगिक संगठनों और समसामयिक घटनाक्रमों से जुड़ा माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा अनियमितता प्रकरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर भी विचार हो सकता है. 6 जुलाई को प्रस्तावित राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के निष्कर्षों के बाद वहां की व्यवस्थाओं को लेकर संघ स्तर पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और लंबे सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है. ऐसे में उसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सभी संबंधित पक्षों की प्राथमिकता होगी.

यह होंगे शामिल

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल, सी. आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त जी, आलोक कुमार, अतुल लिमये सहित अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में भाग लेने वाले हैं.

अब उज्जैन के त्रिनेत्र से दुनिया देखेगा भारत

- राष्ट्रीय पुरस्कार से गौरवान्वित हुई महाकाल की नगरी उज्जैन
- ऐसे सम्मान देते हैं नई ऊर्जा और दोगुनी कार्यशक्ति
- महाकाल मंदिर की त्रिनेत्र परियोजना रंग लाई
- जयपुर में कलेक्टर रोशन सिंह ने किया प्रतिनिधित्व

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी उज्जैन को राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है. जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जयपुर में पुरस्कार प्राप्त किया. इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया संस्था ने संकेत दिए हैं कि उज्जैन की त्रिनेत्र परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे. इसके बाद उज्जैन में विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यह स्वदेशी निगरानी प्रणाली देश विदेश के अन्य शहरों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था का आधार बनेगी. कुल मिलाकर उज्जैन के त्रिनेत्र से भारतीय अब दुनिया देखेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहा उज्जैन जिला प्रशासन एक और राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने में सफल रहा है. जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में महाकालेश्वर मंदिर में संचालित 'त्रिनेत्र' एकीकृत निगरानी प्रणाली को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 के अंतर्गत स्वर्ण सम्मान प्रदान किया गया. उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए यह सम्मान ग्रहण किया. साथ में महाकाल मंदिर प्रसाद प्रथम कौशिक भी थे.

पुरस्कार संबल देते हैं -सम्मान प्राप्त करने के बाद कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि ऐसे पुरस्कार केवल सम्मान नहीं होते, बल्कि वे आगे और बेहतर कार्य करने का संबल देते हैं तथा कार्य करने की दुगनी शक्ति प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उज्जैन जिला प्रशासन, महाकाल मंदिर प्रबंधन और सभी संबंधित विभागों के अथक परिश्रम, निरंतर सक्रियता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. यह सम्मान आने वाले समय में और अधिक बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा तथा विकास की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा.

रंग लाया त्रिनेत्र -जयपुर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर के राज्यों और जिला प्रशासनों द्वारा प्रशासनिक नवाचारों का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह ने उज्जैन की त्रिनेत्र परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया, जिसकी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने सराहना की. समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह एवं राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कलेक्टर रोशन सिंह को स्वर्ण सम्मान प्रदान किया.

उज्जैन को लगे विकास के पंख

कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन में उज्जैन तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. सिंहस्थ महाकुंभ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य संचालित हैं. सड़क, पेयजल, यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक और आधारभूत संरचना सहित अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, जिससे उज्जैन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है.

पुरस्कारों की लंबी फेहरिस्त रहेगी

कलेक्टर रोशन सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मान उज्जैन के लिए नई शुरुआत है और आने वाले समय में विकास, सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में उज्जैन को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि महाकुंभ-2028 के पूर्व उज्जैन देश और दुनिया के सामने एक विकसित, आधुनिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा. इस दौरान पलाश शर्मा, सचिन जैन एवं आईटी टीम उपस्थित रही.

प्रदेश पुलिस में ई-लीव प्रणाली

विशेष संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस ने पुलिस कर्मियों की सेवा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और पूर्णत: डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एचआरएमएस) का ई-लीव मॉड्यूल लागू कर दिया है.

एक जुलाई से लागू इस नई व्यवस्था के माध्यम से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन, स्वीकृति और अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर लागू की गई यह व्यवस्था कागजी प्रक्रिया को कम करने के साथ-साथ अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी. कर्मचारी अब ई-एचआरएमएस पोर्टल तथा मोबाइल एप के माध्यम से रियल टाइम में अपने अवकाश आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. यह पहल मध्यप्रदेश पुलिस के व्यापक डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2025 में सेवा अभिलेखों के डिजिटलीकरण से हुई थी. मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) के सहयोग से एक लाख से अधिक सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग की जा चुकी है तथा लगभग एक लाख पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है.

ई- नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई- गवर्नेंस पुरस्कार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई-नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत साइबर सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में यह सम्मान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया गया. मप्र को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य की दूरदर्शी नीति और तकनीकी श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण है. मप्र शासन ने न केवल नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ और सुगम बनाया है, बल्कि उन्हें एक अभेद्य सुरक्षा आवरण भी प्रदान किया है. नगरीय निकायों से जुड़े लाखों नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत एवं वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पारदर्शी प्रशासन को अक्षुण्ण रखना तथा सुरक्षित आईटी अवसंरचना का निर्माण करना पोर्टल की विशेषता रही है.

मानसून ने पूरे एमपी को किया कवर

भोपाल, 2 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और गुरुवार को उसने प्रदेश के सभी जिलों को कवर कर लिया. राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, रीवा, सीहोर, रतलाम, दमोह और पांढुर्णा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई.

दमोह में लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए, जबकि कई शहरों में दिनभर रुक-रुककर तेज वर्षा होती रही. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेशभर में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

इस वर्ष मानसून ने 24 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और लगभग नौ दिनों में पूरे प्रदेश में फैल गया. हालांकि इसकी एंट्री सामान्य तिथि की तुलना में करीब नौ दिन देर से हुई. इसके बावजूद जुलाई की शुरुआत के साथ मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है.

मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में औसतन 100.2 मिमी (करीब चार इंच) वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 139.7 मिमी होनी चाहिए थी.

फिलहाल प्रदेश में लगभग 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि विभाग का अनुमान है कि जुलाई में तेज बारिश का सिलसिला इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है. विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है.

नाबालिग छात्र को बंधक बनाकर पीटा

मुरैना, 2 जुलाई. जिले के सुमावली थाना क्षेत्र में प्रेम संबंधों के शक में एक नाबालिग छात्र को बंधक बनाकर बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो सुमावली कस्बे के मेला ग्राउंड क्षेत्र का है. वीडियो में दो युवक एक नाबालिग छात्र के पैर रस्सी से बांधकर डंडों से उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया. वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की. सुमावली थाना प्रभारी रवी प्रताप सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चौखुटी गांव निवासी नाबालिग छात्र का गांव की ही एक नाबालिग लड़की से प्रेम संबंध होने का संदेह था. छात्र मुरैना से कोचिंग कर अपने घर लौट रहा था.

पेज एक का शेष

मंत्रिमंडल व संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा

सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में किसी वरिष्ठ नेता को उपप्रधानमंत्री नियुक्त करने के राजनीतिक फायदों को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है .बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अमित शाह व राजनाथ सिंह में से किसी को उप प्रधानमंत्री की कुर्सी देकर सरकारी कार्यों को और सुव्यवस्थित करने का फैसला हो सकता है. इतना ही नहीं चर्चा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब व हिमाचल समेत 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यानी मिशन 2027 के लिए भी इस महामंथन में विस्तृत समीक्षा की गई है ताकि चुनावी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए संगठन और सरकार में जिम्मेदारियों का आवंटन किया जा सके. सूत्र बता रहे हैं कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में विपक्षी दलों से पाला बदलकर आए सांसदों को मंत्री पद का इनाम दिया जाए या संगठन के पुराने वफादारों को तरजीह दी जाए, इस पेंच को सुलझाने के लिए इस बैठक में एक विशेष सोशल-इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है.

नरोत्तम को चुनौती दे सकते हैं अनुज भारती

वहीं उनको कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती के पुत्र अनुज भारती चुनौती दे सकते हैं. उपचुनाव में इन दोनों ही दलों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है. हांलाकि नाम अंतिम रूप से तय करने से पहले दोनों ही बड़े दलों के बीच रायशुमारी से लेकर पैनल तैयार करना और फिर उस पर स्वीकृति की मुहर लगाने की औपचारिकता भी होगी. लेकिन ये सब रस्मी ही होने की संभावना है. दोनों ही दलों के उम्मीदवार लगभग तय है.

क्यों है दोनों नेताओं की दावेदारी मजबूत: डॉ. नरोत्तम मिश्रा भाजपा के बेहद कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होती है. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेन्द्र भारती से नजदीकी मुकाबले में 7742 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. उनकी उम्मीदवारी को अभी दतिया से चुनौती देने के लिए भाजपा में कोई और कद्दावर नेता नहीं है, जो कांग्रेस को सीधी चुनौती दे सके, ऐसे में उनको ही टिकट मिलने की संभावना है. वैसे भी वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं. इधर कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव में चुनौती देने वाले राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता शून्य घोषित हो गई है, जिस कारण उपचुनाव हो रहे हैं. राजेन्द्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यदि किसी विधायक, सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वहीं वे 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित हो जाते हैं. भारती फिलहाल अगले 9 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. अभी तक कोर्ट से उन्हें कोई स्टे नहीं मिला है. ऐसे में राजेन्द्र भारती इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे. लिहाजा अब कांग्रेस उनके पुत्र अनुज भारती पर दांव लगा सकती है. कांगेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अनुज भारती ही भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं. उनका ये भी मानना है कि क्षेत्र में राजेन्द्र भारती की जिस तरह से सदस्यता निरस्त की गई, उससे क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति है. इसी सहानुभूति को वोट में तब्दील करने के लिए पिता के बजाय पुत्र पर दांव लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है.

दिलचस्प होगा उपचुनाव: भाजपा संगठन और डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ताकत एक प्लस एक बराबर 11 की ताकत बनाते हैं. लिहाजा ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है. ये उपचुनाव भाजपा और डॉ. मिश्रा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सबब बन गया है. भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापस कब्जा करना चाहेगी. इधर कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सहानुभति की लहर पर सवाल कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा को नजदीकी चुनौती पेश कर सकती है. पिछला चुनाव परिणाम भी बेहद नजदीकी रहा था, ये उपचुनाव भी नजदीकी रह सकता है.

चुनाव आचार संहिता लागू: उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित होते ही दतिया जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

नर्मदा क्षेत्र विकास के निर्णय अब हर माह

- हर माह होगी नर्मदा समग्र की बैठक
- नर्मदा परिक्रमा पथ अतिक्रमण मुक्त होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवन रेखा है. यह आबादी नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर ही निर्भर है. नर्मदा हमारी धार्मिक आस्था, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है. इसे हर तरह से निर्मल और अविरल बनाए रख कर नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए. प्रदेश में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जायें.

नर्मदा और इसकी सहायक नदियों सहित पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए समाज को विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाये. उन्होंने कहा कि अब हर महीने नर्मदा समग्र की बैठक में इस नदी क्षेत्र के विकास के निर्णय लिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां नर्मदा के

विकास से जुड़ना एक पवित्र काम है. सभी विभाग के अधिकारी पूरे समर्पण से यह काम करें. उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ को पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त कर पथिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाये और परिक्रमा मार्ग पर संकेतक भी लगाए जाए.

18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन होंगे

बैठक में एसीएस शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि नर्मदा नदी के सीमावर्ती प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन किए जाएंगे. मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य, गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे. बैठक में एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि मां नर्मदा के जल को सदैव निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा नमन मिशन तैयार किया गया है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60